हिंदी सांध्य दैनिक

भवानी टाईम्स

प्रधान संपादक : चंद्रकांत खंडेलवाल, 9422831140

RNI Reg.NO.39851/1981

E-mail : bhawanitimes@gmail.com

वर्ष : 46 अंक : 40 गोंदिया, रविवार दि. 12 जुलाई 2026 पृष्ठ : 04 मूल्य : 1.10 रू Post Redg.NPMFL/27/2024-2026

बेर के पेड़ को लेकर कुल्हाड़ी से हमला

गोंदिया : तिरोड़ा थाने के तहत खेडेपार गांव में बेर के पेड़ को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार, खेड़ेपार निवासी फिर्यादी सतीश गोविंदराव मानकर (37) का आरोप है कि गांव के मोतीराम रामलाल पटले (70) अपने खेत में स्थित बेर का पेड़ काट रहा था. जब शिकायतकर्ता की मां ने उसे पेड़ काटने से रोका तो आरोपी कथित रूप से गालीगलौज करते हुए कुल्हाड़ी लेकर मारने दौड़ पड़ा. बीचबचाव करने पहुंचे फिर्यादी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया गया.

संक्षिप्त

श्वानों से नागरिकों में खौफ

तिरोड़ा : शहर के नागरिक लावारिस श्वानों के झुंड से परेशान है. इनका झुंड एक दूसरे से किस समय भीड़ जाएगा यह बताया नहीं जा सकता. शहर के अनेक स्थानों सहित हर क्षेत्र में श्वानों का झुंड मार्ग पर होता है. इसमें कई बार वाहन चालकों के पीछे श्वान दौड़ते है जिससे कई नागरिक इनके हमले में घायल हो गए है.

पशु उपचार के लिए किसान परेशान

गोंदिया : सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को समय पर अपने पशुओं का इलाज करने के लिए पशु चिकित्सालय स्थापित किए हैं. लेकिन तहसील के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित पशु अस्पताल में इलाज करने वाले डाक्टर, पशुधन पर्यवेक्षक, परिचारक आदि उपलब्ध नहीं होने के कारण ये अस्पताल नाममात्र के ही रह गए है और पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ रहा है.

स्पीड ब्रेकर दुर्घटना का कारण

गोंदिया : जिन सड़कों की हालत थोड़ी ठीक है वहां पर अमानक स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं. जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. नागरिकों की सुविधा के लिए बने स्पीड ब्रेकरों ने चिंता और बढ़ा दी है. अमानक स्पीड ब्रेकर से गुजरने पर लगने वाले झटकों से बीमारी का खतरा बढ़ रहा है. नगर की मुख्य सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकर में नियमों को तो ताक पर रखा है.

गोदाम से 95,200 रु. की सामग्री चोरी

गोंदिया : रामनगर थाने के तहत सुर्याटोला निवासी राहुल वसंतराव गारसे (39) के स्टार किराणा गोदाम से अज्ञात व्यक्ति ने एम्पली फायर मशीन, डिजिटल क्रास ओवर डिबीएक्स ऐसा कुल 95 हजार 500 रु. का माल चुरा लिया. रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच सहायक फौजदार राजेश भुरे कर रहे हैं.

अनुमति से पहले ही शुरू हो गया मातोश्री सडक का निर्माण

संबंधित ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के कामकाज पर उठने लगे हैं सवाल

संवाददाता / गोंदिया

जिले की गोरेगांव तहसील में मातोश्री पैदल सड़क योजना के तहत एक गंभीर अनियमितता सामने आई है. किसानों की सुविधा के लिए बनाई जा रही इस सड़क का निर्माण आवश्यक प्रशासनिक अनुमति मिलने से पहले ही शुरु कर दिया गया. हैरानी की बात यह है कि करीब 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह मामला उजागर हुआ. इस घटना के बाद संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय नागरिकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

मातोश्री पैदल सड़क योजना का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों तक सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध कराना है. गोरेगांव तहसील के बोरगांव, सुखपुर, नवरगांव, बघोली और चोपणटोली आदि गांवों के किसानों को खेतों तक पहुंचने में सुविधा के लिए यह सड़क बनाई जा रही थी. संबंधित क्षेत्र में गुमडोह जलाशय परियोजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग की नहर भी मौजूद है, जिसके किनारे सड़क का निर्माण किया जा रहा है. नियमों के अनुसार सिंचाई विभाग की नहर या उसकी मेड पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले संबंधित विभाग से अनापत्ति (एनओसी) और प्रशासनिक मंजूरी लेना अनिवार्य होता है. लेकिन इस मामले में बिना अंतिम स्वीकृति प्राप्त किए ही ठेकेदार ने सड़क निर्माण शुरु कर दिया. बताया जा रहा है कि जब तक मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया, तब तक लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था. इसके बाद सिंचाई विभाग ने निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए.

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि बड़ी राशि के निर्माण कार्य का लाभ लेने के उद्देश्य से नियमों की अनदेखी की गई. लोगों का कहना है कि मंजूरी मिलने का इंतजार किए बिना ही निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया, जिससे सरकारी प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई. यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित ठेकेदार के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सकती है. ग्रामीणों और किसानों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है.

उनका कहना है कि यदि बिना अनुमति सरकारी भूमि और नहर की मेड पर निर्माण किया गया है, तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है. नागरिकों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की है. फिलहाल संबंधित विभागों द्वारा मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होने की संभावना है.

खेत के कुएं में मिला बाघ का शव

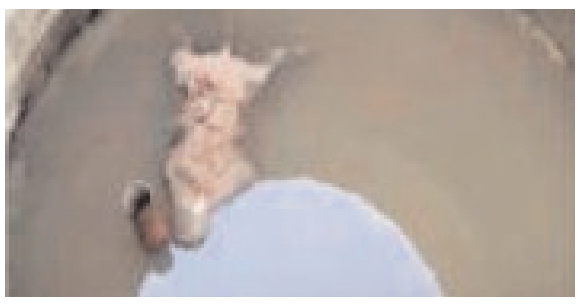

संवाददाता / गोंदिया

गोरेगांव तहसील के सड़क अर्जुनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत मुरदोली के खेत परिसर में स्थित कुएं में बाघ का शव दिखाई देने की घटना शनिवार 11 जुलाई को शाम 5 बजे के दौरान सामने आयी। इस घटना से वन्यजीव प्रेमी व नवेगांव-नागझिरा अभयारण्य विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एनएनटीआर की टीम घटनास्थल पर पहुंची। बाघ के शव को निकालने की प्रक्रिया समाचार लिखे जाने तक चल रही थी। बता दें कि नवेगांव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के बफर जोन क्षेत्र में मुरदोली ग्राम आता है, जो घने जंगलों से सटा हुआ है। बाघ इस परिसर में विचरण करते हुए कई बार दिखाई दिए हैं। मुरदोली निवासी रोशनलाल कटरे धान की फसल देख रहे थे इसी दौरान कुएं में बाघ का शव दिखाई दिया। घटना की जानकारी एनएनटीआर के अधिकारियों को दी। बता दें कि किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई कुओं का निर्माण किया है, लेकिन कुएं के चारों ओर कोई सुरक्षा दीवार या मुंडेर नहीं होने के कारण यह खुले कुएं वन्यजीवों के मौत के कारण भी बन रहे हैं।

सड़क अर्जुनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत मुरदोली की घटना

स्कूल में टॉयलेट बनाए, लेकिन चेंबर नहीं

संवाददाता / गोंदिया

शासन की ओर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरा परिसर स्वच्छ रहे और कोई भी खुले में शौच ना करे। इस अभियान पर करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष खर्च किये जा रहे हैं,

लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा रही है। गोंदिया नगर परिषद के नियंत्रण में संचालित रामनगर में स्थित मराठी, हिंदी प्राथमिक शाला में टॉयलेट तो बनाए गए हैं, लेकिन उपयोग कर नहीं सकते। जिस वजह से स्कूल के शिक्षक और कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में अपने घर जाना पड़ता है। इस तरह की स्थिति कई महीनों से है। लेकिन

इस ओर न तो शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है ना ही गोंदिया नगर परिषद प्रशासन। शाला में रामनगर क्षेत्र के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यहां टॉयलेट का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसकी मुख्य वजह टॉयलेट के लिए चेंबर की व्यवस्था व पानी का प्रबंधन नहीं किया गया है। यहां तक की छत के बजाय टीन लगा दी हैं।

वह भी गल चुकी हैं और एक गायब हो गई है। साथ ही टॉयलेट पूरी तरह से चोक हो जाने से कोई भी इसे उपयोग नहीं कर सकता। जिस वजह से शिक्षक- कर्मचारी व विद्यार्थियों को स्कूल छोड़कर अपने-अपने घर की ओर रुख करना पड़ता है।

तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा के वडेगांव पीएचसी व क्वार्टर निर्माण को 2026-27 की पीआईपी में शामिल करने की मांग

विधायक विजय रहांगडाले ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा पत्र

संवाददाता / तिरोड़ा

तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायक विजय रहांगडाले ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान (एनएचएम) के अधीन आधारभूत सुविधा विकास कक्ष की वर्ष 2026-27 की प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) में वडेगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) एवं कर्मचारियों के आवास (क्वार्टर) निर्माण कार्य को प्राथमिकता से शामिल कर मंजूरी देने की मांग की है। विधायक ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में बताया कि वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 की पीआईपी के अंतर्गत तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के कई स्वास्थ्य अधोसंरचना संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अधीक्षण अभियंता, मुंबई कार्यालय को भेजे जा चुके हैं। इन कार्यों का शीघ्र पूर्ण होना क्षेत्र के ग्रामीण नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रस्ताव में विशेष रूप से वडेगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 937.50 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित परियोजना को वर्ष 2026-27 की पीआईपी में प्राथमिकता के आधार पर शामिल कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

विधायक रहांगडाले ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध होने से चिकित्सा सेवाएं अधिक प्रभावी और नियमित रूप से संचालित हो सकेंगी। इससे वडेगांव सहित आसपास के अनेक गांवों के हजारों नागरिकों को समय पर उपचार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने राज्य सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को वर्ष 2026-27 की पीआईपी में तत्काल मंजूरी प्रदान करने की मांग की है।

जलवायु परिवर्तन पर मार्गदर्शन

संवाददाता / नवेगांवबांध

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना (पोकरा) चरण-2 अंतर्गत अर्जुनी मोरगांव तहसील के गुढरी में महिला खेती शाला के दूसरे सत्र का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में महिला किसानों को जलवायु परिवर्तन, फसल बीमा, आधुनिक कृषि तकनीक तथा धान की खेती के वैज्ञानिक प्रबंधन संबंधी जानकारी दी गई.

उपकृषि अधिकारी राजेश संग्राम ने एलनीनो के प्रभाव से मौसम में हो रहे बदलाव और अनिश्चित वर्षा की स्थिति में फसलों की सुरक्षा के उपायों पर मार्गदर्शन दिया. वहीं सहायक कृषि अधिकारी योगेश भोयर ने फसल बीमा योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राकृतिक आपदाओं, कीट-रोगों और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई में यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित होता है. योगेश भोयर ने कृषि विभाग के महाविस्तार एआई ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से किसान घर बैठे फसलों की बीमारियां, मौसम की जानकारी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

कार्यक्रम में समूह सहायक राजन सोनग्रे ने धान की नर्सरी प्रबंधन, प्रारंभिक अवस्था में कीट एवं रोग नियंत्रण तथा वैज्ञानिक खेती के तरीकों पर महिला किसानों का मार्गदर्शन करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया.

बिहार और भुसावल से गुम हुईं महिलाएं लौटीं अपने घर

संवाददाता / गोंदिया

गोंदिया स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर की वजह से बिहार और भुसावल से लगभग एक माह से गुमशुदा दो महिलाएं सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच पाई है।

मिली जानकारी के अनुसार बिहार राज्य के नालंदा जिला निवासी 40 वर्षीय रिंकूदेवी राजकुमार साव एक माह से घर से गुमशुदा थी। परिवारजन उसकी तलाश में जुटे थे, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया। 4 जुलाई को गोंदिया जिले के रावणवाड़ी गांव समीप एक महिला भटकते हुए नजर आई, जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर थी। नागरिकों ने तत्काल 112 क्रमांक पर फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त महिला को पुलिस स्टेशन ले गए और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सखी वन स्टॉप सेंटर गोंदिया में भेजा। इसी तरह की दूसरी घटना रामनगर पुलिस थाना की सीमा में घटित हुई। 20 जून 2026 की रात पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान भुसावल निवासी रेखा तुकडीदास राठौड़ नजर आई। जिसकी भी मानसिक

स्थिति कमजोर थी। जो अपने घर की जानकारी उचित रूप से नहीं दे पा रही थी। उसे भी सुरक्षा के लिहाज से सखी वन स्टॉप सेंटर को सौंप दिया गया। इस सेंटर के समुपदेशकों ने दोनों ही महिलाओं को विश्वास में लेकर संवाद साधा। महिलाओं की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर केंद्र के कर्मचारियों ने तकनीकी व पुलिस की सहायता से महिलाओं के परिवारजनों से संपर्क किया। 5 जुलाई को बहार से रिंकूदेवी के परिवार के नागरिक गोंदिया स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर पहुंचे और कागजी कार्यवाही के पश्चात केंद्र प्रशासक मधु बिसेन ने रिंकूदेवी को उसके परिवार को सौंप दिया। उसी प्रकार भुसावल निवासी रेखा राठौड़ को भी परिवार को सौंपकर गंतव्य की ओर रवाना किया। यह कार्यवाही केंद्र प्रशासक मधु बिसेन के मार्गदर्शन में सखी केंद्र के कर्मचारी वैशाली सांगाडे, लीना बुराडे, काजोल करवाडे, भूषण भेलावे, सविन राऊतकर, प्रीति नागरिकर, श्रद्धा कोडे, दुर्गा बेबाम ने की.

संग्रामपुर जलाशय के नवीनीकरण, पंपगृह व राइजिंग मेन कार्य के लिए ६० करोड़ रुपये मंजूर

विधायक विजय रहांगडाले ने जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन का जताया आभार

संवाददाता / तिरोड़ा

तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। धापेवाडा उपसा सिंचन योजना (चरण-2) के अंतर्गत संग्रामपुर जलाशय के नवीनीकरण, पंपगृह, राइजिंग मेन (ऊर्ध्व नलिका) तथा वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 60 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए निधि स्वीकृत होने पर विधायक विजय रहांगडाले ने राज्य के जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन तथा मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया है।

धापेवाडा उपसा सिंचन योजना के माध्यम से वैनगंगा नदी पर निर्मित बैराज से पानी उठाकर विभिन्न जलाशयों में पहुंचाया जाएगा, जिससे भंडारा एवं गोंदिया जिले की लगभग 90,146 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। परियोजना के प्रथम चरण में बैराज का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में कवलेवाडा पंपगृह, सर्रा एवं बोदलकसा राइजिंग मेन के माध्यम से चोरखमारा तथा बोदलकसा

जलाशयों तक पानी पहुंचाने का कार्य प्रस्तावित है। इससे अब तक 8,650 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता विकसित की जा चुकी है। स्वीकृत 60 करोड़ रुपये की राशि से संग्रामपुर जलाशय के मुख्य एवं लघु नहरों का नवीनीकरण, जर्जर संरचनाओं का पुनर्निर्माण, नहरों की लाइनिंग, पंपगृह, राइजिंग मेन तथा वितरण कुंड का निर्माण किया जाएगा। लंबे समय से नहरों में गाद भर जाने, जलसेतुओं के जर्जर होने और वितरण व्यवस्था कमजोर होने के कारण सिंचाई के दौरान पानी का भारी अपव्यय हो रहा था। इस परियोजना के पूर्ण होने से सिंचाई व्यवस्था अधिक प्रभावी और सुचारु हो सकेगी। परियोजना के तहत बरबसपुरा, धामनेवाड़ा, एकोडी, दांडेगांव, रामपुरी, बेर्डीपार, सेजगांव, सहेसपुर, नहरटोला तथा सोनेगांव सहित अनेक गांवों के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। संग्रामपुर जलाशय का मूल सिंचित क्षेत्र 712 हेक्टेयर था, जिसे धापेवाडा उपसा सिंचन योजना के माध्यम से 730 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़कर कुल 1,442 हेक्टेयर तक विस्तारित किया जाएगा।

विधायक विजय रहांगडाले ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी, किसानों को वर्षभर पानी उपलब्ध होगा तथा कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने इसे तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

३ किलो गांजे की तस्करी करते आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

संवाददाता / आमगांव

आमगांव पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 10 जुलाई की रात स्थानीय कामठा चौक पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 किलो 20 ग्राम गांजा लेकर मोटर साइकिल से जा रहे एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी के पास से 1 लाख 51 हजार रुपए का 3 किलो 20 ग्राम गांजा एवं मोटर साइकिल मिलाकर कुल 2 लाख 53 हजार रुपए का माल जब्त किया गया है।

आरोपी का नाम गोंदिया निवासी निलेश दयाराम मेश्राम बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आमगांव पुलिस ने 10 जुलाई की रात कामठा चौक पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक मोटर साइकिल सवार की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई देने पर उसे जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान आरोपी के

पास से गांजा बरामद हुआ। जब्त किया गया गांजा वास्तव में कहां से लेकर आ रहा था? और उसे कहा ले जाया जा रहा था? इसकी जांच पुलिस कर रही है।

गौरतलब है कि आमगांव तहसील मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी से सटा हुआ है। वहीं आगे सालेकसा होकर छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला भी सटा हुआ है। जिसे देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इस क्षेत्र के इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। वैसे भी शहर के अंदर भी युवाओं से नशे का कारोबार किए जाने की भी जानकारी मिली है।

संपादकीय

दवा न बने दारू

सार्वजनिक विमर्श में लंबे समय से मांग की जाती रही है कि ज्यादा अल्कोहल की मात्रा वाली दवाओं का सख्ती से नियमन किया जाए। दरअसल, नशे की लत छुड़ाने के प्रयासों के दौरान इन दवाओं का दुरुपयोग किया जाता रहा है। साथ ही जिन राज्यों में नशाबंदी लागू है, वहां भी उनके गलत इस्तेमाल की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का ज्यादा अल्कोहल की मात्रा वाली पीने वाली दवाइयों व सिरप की बिक्री पर सख्ती करने का फैसला, एक जरूरी सुधार है। निश्चय ही इस कदम से लंबे समय से इन दवाइयों के गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी। दरअसल, १२ प्रतिशत से ज्यादा एथिल अल्कोहल मात्रा के साथ बड़ी बोतल में मिलने वाली दवाइयों के लिये अब लाइसेंस, डॉक्टर की पर्ची और रिकॉर्ड रखने के नियम कड़े करके सरकार ने जरूरी पहल की है। आखिरकार सरकार ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, जिसे रेगुलेटर लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। यह हकीकत है कि इन दवाओं का नियमन व निगरानी कायदे की न होने से ये दवाएं नशा करने का जरिया भी बन रही थीं। निश्चित रूप से ये नये नियम मरीजों की दवा तक पहुंच और जन-सुरक्षा के बीच समझदारी भरा संतुलन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन्हें वास्तव में इन दवाइयों की जरूरत है, उन्हें ये दवाइयां डॉक्टर की देखरेख में सहज उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं दूसरी ओर इन दवाइयों का दुरुपयोग गलत कार्य के लिये करने वालों की इन तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी। निश्चय ही यह वक्त की जरूरत थी क्योंकि किशोर और नशे की लत से जूझ रहे लोग अक्सर ऐसी दवाइयों को शराब के सस्ते विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। जनमानस में उपचार के लिये आम बोलचाल में प्रचलित शब्द 'दवा-दारू', वास्तव में ऐसे नशेड़ियों के लिये नशे का मौका उपलब्ध कराने का जरिया बन जाता था। इस पर अंकुश लगाना निश्चिय ही स्वागत योग्य कदम है।

दरअसल, एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने नशीले पदार्थों की लत छुड़ाने के लिये इलाज करा रहे लोगों के बीच इन दवाइयों व कफ सिरफ आदि के अनुचित इस्तेमाल का पर्याप्त रिकॉर्ड रखा है। इतना ही नहीं, जन स्वास्थ्य से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बाबत चिंता जाहिर कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो बाकायदा चेतावनी दी है कि जिन जगहों पर सामान्य शराब महंगी होती है या नशाबंदी लागू होने से आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, वहां अधिक अल्कोहल वाली दवाइयों के दुरुपयोग की लगातार संभावना बनी रहती है। जो इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि जैसे-जैसे नशीले पदार्थों के रूप में दवाइयों का दुरुपयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे ही नियमों में बदलाव करना अपरिहार्य हो जाता है। बहरहाल, कागजों पर नियम बना देना तो मात्र एक शुरुआत भर है। सबसे जरूरी है कि इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि नियमों को तोड़कर दवा के दुरुपयोग की कोशिश करने वालों की निगरानी के लिये ड्रग इंस्पेक्टरों की पर्याप्त संख्या हो। इसके अलावा फार्मेसियों को भी इस बाबत जवाबदेह बनाना जरूरी हो जाता है। जिसके लिये ऐसी दवाइयों की बिक्री के रिकॉर्ड को डिजिटल करना भी आवश्यक है ताकि नियामक तंत्र इनकी बिक्री की निगरानी कर सके। निस्संदेह, डॉक्टरों का भी नैतिक दायित्व है कि वे जरूरतमंद लोगों को ये दवाइयां सोच-समझकर ही लिखें। साथ ही इससे होने वाले खतरों के बारे में भी मरीजों को अवगत कराएं। इन बोतलों पर दवा का लेबल लगाने का अंतिम निष्कर्ष यह नहीं है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बहरहाल, नियमों में बदलाव सरकार की एक बुनियादी जिम्मेदारी को ही दर्शाता है। जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि इलाज के लिए उपयोग होने वाले उत्पादों से लोगों को फायदा ही हो, नुकसान नहीं। निस्संदेह, सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। अब इस नियम को सख्ती से लागू करने का पक्का इरादा भी दिखाना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस रोग का पूरा इलाज नहीं हो पायेगा।

अमृत योजना के काम में भारी लापरवाही, जान से खिलवाड़

वृद्धा की मौत के बाद ताजनगर के लोगों में करंट का डर

नागपुर : मनपा की तरफ से अमृत-2 योजना अंतर्गत किए गए सीवरलाइन के काम में भारी लापरवाही का मामला समय बीतने के साथ ही सामने आ रहा है. गौसिया कॉलोनी में करंट लगने से मृत 60 वर्षीय महिला के मामले में अब भी जांच जारी है. मनपा ने ठेकेदार दास कंस्ट्रक्शन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया. अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में समिति भी बना दी. इसी बीच ताजनगर के गली नंबर 1 के निवासियों का आरोप है कि अमृत योजना अंतर्गत सीवर लाइन की खुदाई के बाद से ही बारिश होने पर करंट लगने की स्थिति बनती है. उस दौरान भूमिगत बिजली के केबल क्षतिग्रस्त हुए थे. ऐसे में मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से साइट की निगरानी सवालों के घेरे में आ गया है.

ताजनगर के लोगों ने इसकी शिकायत पार्षद रूपाली ठाकुर से की. उन्होंने मनपा के विद्युत विभाग, एमएसईडीसीएल और अमृत योजना के ठेकेदार के अधिकारियों को संबंधित मामले की जानकारी देकर मौके पर बुलाया. अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त भूमिगत केबल को मुख्य बिजली आपूर्ति से अलग करवा दिया और अस्थायी रूप से ओवरहेड बिजली कनेक्शन दिया गया. साथ ही ठेकेदार को अधिकारियों की मौजूदगी में तुरंत खामी दूर करने के निर्देश दिए गए.

ज्ञात हो कि अमृत योजना अंतर्गत 900 करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं. काम की

गुणवत्ता व ठेकेदार पर निगरानी का काम मनपा के सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के

ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करें : ठाकुर

अमृत योजना के तहत सीवर लाइन की खुदाई में बरती गई लापरवाही को गंभीर बताते हुए अग्निशमन समिति की सभापति रूपाली ठाकुर ने कहा कि मनपा प्रशासन को ठेकेदार दास कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए. यदि उस समय तेज बारिश हो जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. सौभाग्य से पानी डाले जाने के बाद यह मामला सामने आ गया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में इस प्रकार की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

शिकायत के बाद भी मरम्मत नहीं की

ताज नगर की गली नंबर-1 में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन की खुदाई के दौरान कई महीने पहले भूमिगत बिजली केबल क्षतिग्रस्त हो गई थी. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद अब तक उसकी मरम्मत नहीं की गई. शनिवार को नागरिकों ने फिर अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि बारिश के कारण जलभराव वाले हिस्सों में करंट फैल रहा था, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की जान खतरे में थी. 70 वर्षीय सरस्वती कैथवास ने बताया कि घर के बाहर चलते समय उन्हें कई बार करंट लगा. उन्होंने कहा कि उनके पोते-पोतियां रोज यहीं खेलते हैं और समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

नागपुर में सप्ताहभर बारिश के आसार नहीं

बादल छंटते ही धूप खिली, तापमान 34.2 डिग्री

नागपुर : नागपुर में जुलाई के शुरुआती कुछ दिनों तक मानसूनी मेघ मेहरबान दिखे। बाद में बादल ऐसे शांत हुए कि जोरदार बारिश को लेकर शहरवासियों का इंतजार बढ़ गया है। आगामी सप्ताहभर खुलकर बारिश के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। नागपुर में शनिवार को दिन का तापमान 34.2 डिग्री पर जा पहुंचा। सामान्य से दो डिग्री अधिक होने से गर्मी का अहसास भी होने लगा।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से बंगाल में बने कम दबाव का क्षेत्र नजर आ रहा है। मध्यभारत में मानसूनी गतिविधियां ठंडी पड़ गई हैं। विदर्भ के कुछ जिलों में 13 से 15 जुलाई के बीच हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। लेकिन भारी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में 14 से 17 जुलाई और छत्तीसगढ़ में 11 से 15 जुलाई के बीच भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। 35.8 डिग्री के साथ चंद्रपुर पूरे विदर्भ में सबसे गर्म रहा। अधिकांश जिलों में

दिन का तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री अधिक बना हुआ है।

नागपुर में सुबह से ही आसमान साफ होने से अच्छी धूप खिली। सुबह आर्द्रता 61 फीसदी दर्ज की गई। धूप और आर्द्रता की वजह से उमसभरी गर्मी का अहसास होता रहा। रात का तापमान भी 24.6 डिग्री रहा। जिसकी वजह से लोगों को फिर से एकबार एसी और कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। भंडारा में पिछले चौबीस घंटे में 7 मिमी बारिश दर्ज की गई।

बूटीबोरी का गांजा पैडलर धराया गया; मुख्य सप्लायर हुआ फरार

नागपुर : नशे के सौदागरों के खिलाफ नागपुर पुलिस की धरपकड़ मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच के मादक पदार्थ विरोधी दस्ते ने धंतोली थाना क्षेत्र के तकिया स्लम एरिया में जाल बिछाकर गांजा बेचने आए एक पैडलर को रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक किलो से अधिक गांजा और मोबाइल जब्त किया है। हालांकि, मुख्य सप्लायर पुलिस की भनक लगते ही फरार होने में कामयाब हो गया। ये कार्रवाई 10 जुलाई की शाम 5 से 7:30 बजे के बीच की गई। मादक पदार्थ विरोधी दस्ते को पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी कि तकिया झोपड़पट्टी इलाके में एक व्यक्ति गांजा बेचने के लिए आने वाला है। ऐसे में पुलिस टीम ने इंडियन जिमखाना के पास स्थित खुले मैदान में घेराबंदी कर जाल बिछाया। कुछ ही देर में वहां एक संदिग्ध युवक बैग लेकर पहुंचा। पुलिस ने उसे धर दबोचा।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम निखिल लहू हटीटेल (26), कनालगांव, सातगांव, तहसील बूटीबोरी निवासी बताया। उसके बैग की तलाशी में 1 किलोग्राम 123 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ में निखिल ने बताया कि वह अपने फायदे के लिए गांजा बेचने आया था और ये उसे तकिया, धंतोली निवासी उसके साथी खुशाल मरसकोल्हे ने उपलब्ध कराया था। पुलिस ने खुशाल को इस मामले में वांटेड बनाया है। इस मामले में दोनों आरोपियों पर धंतोली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी निखिल को आगे की जांच और रिमांड के लिए माल के साथ धंतोली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस फरार आरोपी खुशाल की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

वर्धा विभाग से दौड़ेंगी महामंडल की 120 बसें

आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर के लिए एसटी बस सेवा
अब तक १० बसों की अग्रिम बुकिंग, पांच डिपो से शुरू होगी सुविधा

वर्धा : आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) के वर्धा विभाग ने विशेष बस सेवा की तैयारी शुरू कर दी है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वर्धा विभाग के पांच डिपो से विशेष बसों का संचालन किया जाएगा. अब तक 10 विशेष बसों की अग्रिम बुकिंग पूरी हो चुकी है, जबकि मांग बढ़ने पर अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध कराई जाएंगी. वर्धा विभाग के अंतर्गत आने वाले वर्धा, पुलगांव, हिंगणघाट, आर्वी और तलेगांव डिपो से पंढरपुर के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी.

हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों वारकरी और श्रद्धालु आषाढ़ी एकादशी पर विठ्ठल-रुक्मिणी के दर्शन के लिए पंढरपुर रवाना हो रहे हैं. जहां कई श्रद्धालु पैदल दिंडी के साथ यात्रा कर रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और परिवार के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा के लिए एसटी बस सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं. एसटी प्रशासन ने इस वर्ष लगभग 120 विशेष बसें चलाने की तैयारी की है.

यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी. समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनकी यात्रा अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक हो सके. एसटी प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे संबंधित डिपो प्रबंधक अथवा बस स्टैंड प्रमुख से संपर्क कर समय रहते अपनी सीट आरक्षित कर लें. प्रशासन का कहना है कि एसटी बस सेवा सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती यात्रा का सबसे बेहतर विकल्प है.

चोरों के गिरोह को दबोचा तीन मामलों का खुलासा

वणी : शहर में हाल ही में हुई सेंधमारी और चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए वणी पुलिस के डीबी (डिटेक्शन ब्रांच) दस्ते ने पांच सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में सुमित राजू मानकर (२२), राहुल उर्फ टिकल्या नीलकंठ ठेंगणे (३२, रंगनाथ नगर, वणी), विजय देवानंद मेश्राम (३२, लालगुडा) तथा दो महिला आरोपी शामिल हैं. थाना प्रभारी भानुदास पिदुरकर के मार्गदर्शन में डीबी दस्ता गश्त पर था. इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने सेंधमारी, चोरी के प्रयास तथा बैटरी चोरी से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. यह कार्रवाई प्रभारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी रॉबिन बंसल तथा थाना प्रभारी भानुदास पिदुरकर के मार्गदर्शन में की गई. अभियान में डीबी दस्ते के प्रमुख पुलिस उपनिरीक्षक सैय्यद साजिद, गजानन सावसाकड़े, मारोती पाटिल, नीलकमल भोसले, गणेश मेश्राम, नंदकुमार पुप्पलवार, मानेश्वर खंदरे, रितेश भोयर, चालक शुभम किनाके तथा महिला पुलिस कर्मी चैताली चेंडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ब्रह्मपुरी डिपो में शामिल हुईं पांच नई बसें

ब्रह्मपुरी: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) के ब्रह्मपुरी डिपो में 'राजमाता जिजाऊ' नामक पांच नई बसें शामिल हो गई हैं. इन बसों का लोकार्पण हाल ही में हुआ. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के पास विधायक विजय वडेट्टीवार द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्रह्मपुरी डिपो को ये नई बसें प्राप्त हुई हैं. इससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी.

ब्रह्मपुरी डिपो परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में नगराध्यक्ष योगेश मिसार, नगर परिषद उपाध्यक्ष डॉ. नितिन उराडे, स्वास्थ्य सभापति मनोज कावले, नगरसेवक राकेश पडोले, पुष्पाकर बांगरे, वकार खान, अविनाश राऊत, मनोज भूपाल, अमिताभ नागमोती, मुकुंदा राऊत, प्रभारी डिपो प्रबंधक वासनिक तथा यातायात निरीक्षक राजू पांडव उपस्थित थे. इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने नई बसों की उपलब्धता पर संतोष व्यक्त करते हुए विधायक विजय वडेट्टीवार द्वारा ब्रह्मपुरी डिपो के विकास के लिए किए गए निरंतर प्रयासों की सराहना की. कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए राज्य परिवहन सेवा

जीवनरेखा के समान है. नई बसों के शामिल होने से डिपो की यात्री परिवहन क्षमता बढ़ेगी, पुरानी बसों पर दबाव कम होगा तथा विभिन्न मार्गों पर बस सेवाएं अधिक नियमित, प्रभावी और विश्वसनीय बन सकेंगी.

ब्रह्मपुरी पूर्वी विदर्भ का शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र है. चंद्रपुर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा के लिए और मरीज उपचार के लिए प्रतिदिन ब्रह्मपुरी आते-जाते हैं. इसी कारण ब्रह्मपुरी डिपो से अनेक मार्गों पर नियमित बस सेवाएं संचालित होती हैं. यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए लंबे समय से डिपो में नई बसों की मांग की जा रही थी. इस मौके पर डिपो के अधिकारी, यांत्रिक विभाग एवं प्रशासनिक कर्मचारी, चालक, परिचालक तथा कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताएं

विधायक विकास ठाकरे ने विधानसभा में उठाया मुद्दा, जांच की मांग

नागपुर : विधायक विकास ठाकरे ने आरोप लगाया है कि नागपुर सुधार प्रन्यास और द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई हैं. उन्होंने कहा कि निकृष्ट स्तर का निर्माण कार्य हुआ है. लाभार्थियों को घर नहीं मिल रहे. ढांचागत सुविधाओं की कमी है.

विकास ठाकरे ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए यह दावे किए. उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2016 में आरंभ हुई. मनपा को

योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया. तब 75 हजार से अधिक नागरिकों का पंजीयन हुआ. लेकिन आकलन के अनुसार नागपुर शहर में घर की चाहत रखने वाले लाभार्थियों की संख्या दो लाख से अधिक होगी.

इसके बावजूद गत 10 वर्षों में पांच हजार से भी कम लाभार्थियों को आवास मिला. मनपा में हुए पंजीयन को खारिज कर पुनः आवेदन करने को कहा जा रहा है. कागजात एकत्र करने के लिए नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे थे. मौजा तरोडी (खुर्द) के खसरा क्रमांक 62 एवं 63 में नासुप्र से 2021 से 2023 तक करीब 3500 फ्लैट बनाए. लेकिन परियोजना के रास्ते एक साल में ही खराब हो गए. कई फ्लैट में पानी का रिसाव होता है. हल्की सी भी वर्षा में जलजमाव होता है. पेयजल की समस्या है.

आवश्यक होने पर भी सार्वजनिक कुएं का विकास अब तक नहीं हुआ है. उधर मेंटेनेंस शुल्क के नाम पर हर लाभार्थी से 25 हजार रुपए वसूल किए गए हैं. यह शुल्क अब तक गृहनिर्माण संस्था को हस्तांतरित नहीं हुआ है.

बीयर शॉपी को अनुमति कैसे?

ठाकरे ने कहा कि एनआईटी की लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए कुछ दुकानों को बीयर शॉपी और बार आरंभ करने की अनुमति दी गई है. उन्होंने विधानसभा में कहा कि नियमों के उल्लंघन, निकृष्ट स्तर के काम और कार्यों में विलंब की शिकायतों के बाद भी ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जा रहा है.

8 साल की बच्ची से अश्लील हरकत

संवाददाता । नागपुर

हुड़केश्वर पुलिस थाने के तहत सहेली के घर से वापस लौट रही 8 वर्षीय बच्ची के अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी चिंचभवन, स्वामीपुरम सोसायटी निवासी कुबेर अनिल पोहाने (20) है. कुबेर मूलतः पठानपुरा वार्ड, चंद्रपुर का रहने वाला है. यह घटना 24 जून 2026 की रात करीब 9 बजे हुई. पीड़ित बच्ची रात करीब 9 बजे पड़ोस में स्थित अपने रिश्तेदार के घर गई थी. इसी दौरान करीब 30 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति मोपेड पर आया और बच्ची से बातचीत कर उसे अपने साथ ले गया. आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की. जिसके बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता के माता-पिता काम के सिलसिले में 3 दिन तक घर से बाहर थे, जिसके कारण शिकायत दर्ज करने में देरी हुई.

पीड़िता के बयान के आधार पर हुड़केश्वर पुलिस ने भा.न्या.सं. की धारा 74, 75 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8,12 के तहत दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद मानेवाड़ा चौक, शताब्दी नगर चौक, जयप्रकाश नगर, जयताला, हिंगणा रोड, वाईसीसी कॉलेज चौक तक करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई. जिसके बाद पुलिस को आरोपी की मोपेड गाड़ी के नंबर का पता चल गया. आखिर 15 दिन के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनामिका मिर्जापुरे, पुलिस निरीक्षक पवन रामटेके सहित हुड़केश्वर पुलिस टीम ने की.

एसटीपी ठेकेदार पर मनपा के अधिकारी-पदाधिकारी मेहरबान

कछुआ चाल पर कार्रवाई नहीं, 6 माह का अल्टीमेटम, आयुक्त की सुस्ती बनी चर्चा का विषय

संवाददाता । चंद्रपुर

ऐतिहासिक रामाला तालाब में जमा होने वाले सीवेज के प्रसंस्करण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत रामाला तालाब पुनरुद्धार परियोजना 30 करोड़ रु की लागत से शुरू की गई थी. परियोजना के 18 महीने बीत जाने के बाद भी इसकी धीमी गति है. कछुआ चाल को देखते हुए चंद्रपुर नगर निगम के उप महापौर प्रशांत दानव और स्थायी समिति सभापति मनस्वी गिऱ्हे ने अधिकारियों को काम तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया और संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि परियोजना का काम अगले 6 महीनों में पूरा करें अन्यथा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

लेकिन रामाला तालाब एसटीपी परियोजना को लेकर मनपा अधिकारी-पदाधिकारी की ठेकेदार पर मेहरबान चर्चा का विषय बन गया है. ठेकेदार के कछुआ चाल के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, 6 माह का अल्टीमेटम दिया गया है, जिससे पदाधिकारियों का ठेकेदार प्रेम चर्चा का विषय बन गया है.

चंद्रपुर नगर निगम के उप महापौर प्रशांत दानव और स्थायी समिति की अध्यक्ष मनस्वी गिऱ्हे ने नगर निगम के शहर अभियंता रवींद्र हजारे और उप अभियंता सागर सिडाम के साथ मंगलवार को परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए निरीक्षण किया. उपस्थित ठेकेदार से काम की धीमी गति के बारे में सवाल किए गए. ठेकेदार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. फिर भी उप महापौर प्रशांत दानव और स्थायी समिति की अध्यक्ष मनस्वी गिऱ्हे ने ठेकेदार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि परियोजना का काम अगले 6 महीनों में पूरा करने अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया.

काम पूरा होने के बाद तुरंत सड़क मरम्मत हो

मनपा आयुक्त ने सीवेज परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया

संवाददाता । चंद्रपुर

आयुक्त ने अमृत 2.0 के अंतर्गत चंद्रपुर शहर के लिए सीवेज जल निकासी परियोजना के कार्यों के पूरा होने के बाद भिवापुर वार्ड, हिंगलाज भवानी क्षेत्र, एकोरी वार्ड और माता नगर क्षेत्रों में चल रहे सड़क मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया और समीक्षा की.

निरीक्षण के दौरान, आयुक्त ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश के मौसम को देखते हुए, जिन सड़कों पर सीवेज का

काम पूरा हो चुका है, उनकी तुरंत मरम्मत की जाए. नई खुदाई न की जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क बहाली का सारा काम प्राथमिकता के आधार पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए ताकि बारिश के कारण सड़कें कीचड़युक्त और जलभराव वाली न हों और नागरिकों और वाहनचालकों को असुविधा न हो.

69 किलोमीटर का सीवेज कार्य पूर्ण हुआ

चंद्रपुर शहर के लिए अमृत 2.0 सीवेज परियोजना के तहत कुल 69 किलोमीटर सीवेज कार्य पूर्ण हो चुका है. इसमें से 47 किलोमीटर सड़कें सीमेंट-कांक्रीट की हैं, जिनमें से 43 किलोमीटर सड़क मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है.

शेष 4 किलोमीटर कांक्रीट सड़क मरम्मत का कार्य प्रगति पर है. इसके अलावा, शेष 22 किलोमीटर सड़कें कच्ची होने के कारण, उन स्थानों पर जीएसबी (ग्रेन्युलर सब बेस) बिछाकर सड़कों को यातायात योग्य बना दिया गया है. आयुक्त ने संबंधित एजेंसियों को सभी शेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने और नागरिकों की असुविधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है.

नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए शेष सभी सड़क पुनर्निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए. इस अवसर पर मानसून के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए. निरीक्षण के दौरान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी, चंद्रपुर नगर निगम के अधिकारी और संबंधित ठेकेदार उपस्थित थे.

परिसर में बेकार दवाइयों का सामान बिखरा, दुर्गंध से ग्रामीण परेशान

तीन महीने से बंद है वडाला पशु चिकित्सालय

संवाददाता । आष्टी-शहीद

तहसील के अंतिम छोर पर स्थित तथा शहीद वीरों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध वडाला गांव का पशु चिकित्सालय पिछले तीन महीनों से बंद होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है. इससे क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों में भारी नाराजगी है.

ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल परिसर में बेकार दवाइयों और चिकित्सा सामग्री का ढेर बिखरा पड़ा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और स्वच्छता की समस्या भी गंभीर हो गई है. वडाला तथा आसपास के गांवों में पशुपालन अनेक परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है. आदिवासी, भोई, कुणबी सहित विभिन्न समाजों के किसान बड़ी संख्या में खेती के साथ ही मवेशी पालते हैं. ऐसे में समय पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है.

ग्रामीणों के अनुसार कुछ माह पहले अस्पताल की रंगाई-पुताई कर उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया था. लेकिन भवन के नवीनीकरण के बाद भी नियमित पशु चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से सरकारी खर्च पर सवाल उठ रहे हैं.

कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

पूर्व उपसरपंच सहित कई ग्रामीणों ने संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है. किसान रवींद्र वडास्कर ने बताया कि अस्पताल में नियमित सेवा शुरू कराने के लिए जनप्रतिनिधियों से भी कई बार संपर्क किया गया, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, अस्पताल परिसर की सफाई कराई जाए तथा पशुपालकों को निर्बाध पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं.

स्मार्ट मीटर के खिलाफ करेंगे आंदोलन

संवाददाता । गडचिरोली

महावितरण द्वारा चामोर्शी तहसील में बिजली ग्राहकों को पूर्व सूचना न देते हुए मनमानी ढंग से पुराने बिजली मीटर बदलाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे है. इस गंभीर मामले के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने आवाज उठाया है. वहीं इसके खिलाफ जनआंदोलन करने की चेतावनी राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के डा. प्रणय खुणे ने दी है.

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने तहसील के घोट परिसर के गांवों का दौरा किया. जहां ग्रामीणों ने पदाधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराते ग्रामीण परिसर में महावितरण द्वारा जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायत की. वहीं ग्रामीणों कहां कि, नये स्मार्ट मीटर के कारण जिन ग्राहकों को पहले 500 रूपये बिजली बिल आता था, वह अब 5 हजार रूपयों तक पहुंच गया है. जहां डा. प्रणय खुणे ने कहां कि, मीटर बदलाने के पहले ग्राहकों को दो दिन पहले पूर्व सूचना देना बंधनकारक है. लेकिन किसी भी तरह की लिखित सूचना, एसएमएस, व्हॉट्सएप, ई मेल अथवा अन्य किसी भी माध्यम से पूर्व सूचना न देते हुए ग्रामीण परिसर में स्मार्ट मीटर लगाए गए. ग्रामीणों की शिकायत के बाद महावितरण से मीटर बदलाने के पहले पूर्व सूचना देने का लिखित सबूत पेश करने की मांग की गई है. वहीं पूर्व सूचना न देने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों की जांच कर नियमभंग का मामला दर्ज करने, शिकायत पर नियमनुसार लिखित निर्णय देने और भविष्य में ग्राहकों के अधिकार का उल्लघंन न हो, इस संदर्भ में आवश्यक सूचना देने की मांग की गई. वहीं आगामी 15 दिनों के भीतर नियमनुसार कार्रवाई न होने पर महावितरण के खिलाफ जनआंदोलन करने की चेतावनी भी संगठन ने दी है. इस समय भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश सरकार, भाजपा महामंत्री विकास मैत्र, मानवाधिकार संघटन के महेश विस्वास, विनोद किरमे, राजू सातपुते, पलाश घरामी समेत पदाधिकारी उपस्थित थे.

देह व्यवसाय के ४ अड्डों का भंडाफोड़

संवाददाता । वर्धा

पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने जिले में अवैध रुप से चल रहे देह विक्री अड्डों पर कार्रवाई शुरु कर दी है. गत एक माह में चार ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार पीडिताओं को आरोपियों के चंगुल से आजसद कराया तथा मौके से 1 लाख 25 हजार 570 रुपयों का मुद्दे माल जब्त करते हुए 7 आरोपियों के विरुध्द मामला दर्ज कर लिया है. सूत्रों के अनुसार 10 जुलाई को अनैतिक मानवी प्रतिबंधक कक्ष व स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पवनार के मंगलम लॉज पर छापा मारा. जहां से एक महिला को रिहा कराया गया, पवनार निवासी मुरली पुंडलीक पुसतोडे (24) व वर्धा के महादेवपुरा निवासी सुमित गणेश सोदिया (24) दोनों मिलकर यह व्यवसाय चला रहे थे.

यहां बनावटी ग्राहक पुलिस ने भेजा था. इसके बाद मामला उजागर हुआ. लॉज पर एक महिला पायी गई. पूछताछ करने पर रुपयो का लालच देकर उससे देह विक्री का व्यवसाय करवाने की बात सामने आयी. पुलिस ने मौके से कुछ सामग्री, एक मोबाईल व नकद कुल 34 हजार 870 रुपयों का माल बरामद किया. दोनों आरोपियों के विरुध्द सेवाग्राम थाने में मामला दर्ज किया गया. इसके पहले पुलिस ने सावंगी मेघे टी पाइंट पर परिसर में कृष्णाई कोर्ट बिल्डींग, नखाते लेआऊट वैष्णवी कॉम्प्लेक्स कारला रोड परिसर व पवन लॉज भामटीपुरा में भी कार्रवाई को अंजाम दिया था. चारों प्रकरणों में आगे की जांच संबंधित थाने की पुलिस कर रही है.

इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन में एलसीबी के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी, एपीआई माधुरी वाघाडे, पीएसआई गितांजली गारगोटे, पीएसआई दिशा ताजने, पुलिसकर्मी दिनकर परीमल, अमर लाखे, संजयसिंग सुर्यवंशी, चंद्रकांत बुरंगे, संजय राठोड, नितेश मेश्राम, गजानन दरणे, अक्षया सावलकर, शुभांगी निघोट, सोनाली मेसरे, प्रतिभा पेंदाम आदि ने अंजाम दिया

खेतों से मोटर व स्प्रिंकलर की चोरी

आष्टी-शहीद : आर्वी तहसील के जलगांव (बेलोरा) क्षेत्र में खेतों से सिंचाई उपकरणों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. कुछ ही दिनों के भीतर सामने आई दो अलग-अलग चोरी की वारदातों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. पहली घटना में जलगांव (बेलोरा) निवासी सुभाष रामकृष्ण पोटे (71) के खेत की कुएं पर लगी 3 हॉर्सपावर की मोटर चोरी हो गई. शिकायत के अनुसार 28 जून तक मोटर अपनी जगह पर लगी हुई थी, लेकिन 6 जुलाई को खेत पहुंचने पर मोटर गायब मिली. मोटर से जुड़ी बिजली की तार भी कटी हुई पाई गई.

दूसरी घटना में अंकुश रमेश पोटे (35) ने मौजा जलगांव स्थित प्रमिला जनार्दनराव पोटे की 10 एकड़ कृषि भूमि ठेके पर लेकर कपास की खेती की है. फसल की सिंचाई के लिए खेत में 23 सप्रंकलर लगाए गए थे. 7 जुलाई की शाम तक सभी संप्रंकलर सुरक्षित थे, लेकिन 8 जुलाई की सुबह खेत पहुंचने पर 10 प्रिंकलर गायब मिले. लगातार हो रही इन घटनाओं से जलगांव (बेलोरा) क्षेत्र के किसानों में भय और असुरक्षा का माहौल है. क्षेत्र के किसानों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि खेतों में हो रही चोरी की घटनाओं की गंभीरता से जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए तथा किसानों की कृषि संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.

गंजीरामन्नापेठा जिप स्कूल फिर शुरू करें

संवाददाता । गडचिरोली

सिरोंचा पंचायत गंजीरामन्नापेठा में जिला परिषद की प्राथमिक स्कूल को बीते वर्ष से पटसंख्या के अभाव में शिक्षा विभाग ने बंद करने से गांव के शालेय विद्यार्थियों के समक्ष शैक्षणिक समस्या निर्माण हुई है. जिससे विद्यार्थी तथा अभिभावकों में रोष उमड रहा है. इस समस्या को लेकर अभिभावकों ने सिरोंचा तहसील कार्यालय पर दस्तक देकर तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी तथा जिप के मुख्य कार्यपलन अधिकारी को ज्ञापन भेजा है. सिरोंचा तहसील के अंकिसा समीपस्थ गंजीरामन्नापेठा की जिला परिषद प्राथमिक स्कूल बंद किए जाने से शालेय विद्यार्थियों की शिक्षा बंद हुई है. जिससे शालेय विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों में रोष है. जिससे इस शालेय सत्र से उक्त स्कूल पूर्ववत शुरू कर विद्यार्थियों को गांव में ही शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग संतप्त अभिभावकों ने ज्ञापन द्वारा की है. सिरोंचा के नायब तहसीलदार हलामी को यहां के सामाजिक कार्यकर्ते रवि सल्लम व पोचमपल्ली ग्रामपंचायत के पूर्व सरपंच ललिता सल्ला ने अभिभावकों को साथ लेकर स्कूल पूर्ववत शुरू करने के लिए तहसीलदार के कक्ष में चर्चा की. वहीं तहसीलदार के मार्फत जिलाधिकारी व जिप के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन भेजा. अभिभावकों ने ज्ञापन में कहा है कि, सरकार एक ओर 6 से 14 वर्ष उम्रगुट का एक भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, ऐसी बात कह रही है, प्रत्येक विद्यार्थी को निशुल्क व शिक्षा देना अनिवार्य है. लेकिन पटसंख्या के अभाव में संपूर्ण स्कूल ही बंद करना यह अन्यायकारक है.

सुविधा के लिए तरस रहें दुर्गम क्षेत्र के लोग

संवाददाता । गडचिरोली

देश को स्वतंत्र हुए सात दशक की कालावधि पूर्ण हो गयी है. लेकिन जिले की नक्सलग्रस्त एटापल्ली तहसील के अनेक गांव आज भी आजादी की लड़ाई लड़ रहें है. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जिले के विकास हेतु करोड़ों रूपयों की निधि मुहैय्या करायी जाती हैं, लेकिन इसके संचालन हेतु नियुक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय में न रहने के कारण वर्तमान में तहसील के दर्जनों गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है.

जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला समेत अन्य सरकारी कार्यालय निर्माण किए गये हैं. लेकिन इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय में न रहते हुए अन्य गांवों से प्रति दिन आवागमन कर रहें है. जिससे स्थानीय स्तर के विकास कार्य प्रभावित हो रहें है.

गांवों में निर्माण किए गए पशु चिकित्सालयों में कोई डाक्टर उपस्थित न रहने से किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. तहसील के अधिकत्तर गांवों के अस्पतालों में अथवा उपकेंद्रों में डाक्टरों व कर्मचारियों को रहने पर सख्ती के आदेश नहीं दिये जा रहें है. प्राथमिक शालाओं की हालत भी ठीक इसी तरह है. तहसील के अनेक गांवों तक पहुंचने के लिये पक्की सड़के नहीं बन पायी है. किंतु तहसील के विकास की ओर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी होने के कारण अब तक इस तहसील का विकास नहीं हो पाया है.

आंगनवाड़ी कर्मियों की पंचायत समिति पर दस्तक

संवाददाता / गड़चिरोली

कोरोना काल में किए गए कार्य के बदले प्रति माह 1,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता तत्काल दिए जाने की मांग को लेकर आरमोरी पंचायत समिति कार्यालय के सामने आयटक से संबंधित आंगनवाड़ी सेविका तथा मददनीस संगठना की ओर से प्रदर्शन करते हुए राज्य सचिव कॉमरेड देवराव चवड़े के नेतृत्व तथा भाकपा के राज्य परिषद सदस्य तथा किसान सभा के राज्य कार्याध्यक्ष डा. महेश कोपुलवार की उपस्थिति में आंदोलन कर संवर्ग विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना महामारी के दौरान आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपने और अपने परिवार की परवाह किए बिना घर-घर जाकर सर्वेक्षण किए तथा सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 से संबंधित सभी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन किया. इसके बावजूद सरकार द्वारा प्रति माह 1,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने की घोषणा और कई बार निर्देश जारी होने के बाद भी आज तक यह राशि कर्मचारियों को नहीं मिली है. आंदोलन के बाद संवर्ग विकास अधिकारी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायतों को आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया कि कोरोना काल के दौरान प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कोविड-19 संबंधी विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं और उन्होंने ग्राम स्तर पर अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है.

1,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन भत्ता दें: इसलिए जिला स्तर के निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायतें ग्राम निधि अथवा 15 वें वित्त आयोग के उपलब्ध निधि से प्रति माह 1,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन भत्ता चरणबद्ध तरीके से भुगतान करें तथा नियमानुसार कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट पंचायत समिति कार्यालय को प्रस्तुत करें. प्रशासन की ओर से आदेश जारी होने के बाद आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की और कहा कि लंबे समय से लंबित उनकी मांग पूरी होने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है. इस अवसर पर रोहिदास फुलझले, चुन्नीलाल मोटघरे, सचिन जांबेवार, रेखा जांभुळे, प्रेमिला माने, अल्का लाडूकर, रुपाली क्षीरसागर, दुर्गा कुर्वे, कविता चन्ने, माधुरी रामटेके, मीरा उइके, हिरकन्या ढवले, सुनीता निनावे सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी सेविकाएं तथा मददनीस उपस्थित थीं.

बाघिन टीएफ-1 ने दिया फिर 4 शावकों को जन्म

गिरड़-खुर्सापार क्षेत्र में बाघ संरक्षण को मिली नई मजबूती

संवाददाता / समुद्रपुर

वर्धा जिले के समुद्रपुर तहसील के गिरड़-खुर्सापार वन क्षेत्र में बाघ संरक्षण को बड़ी सफलता मिली है. यहां प्रसिद्ध बाघिन टीएफ-1 ने दूसरी बार चार शावकों को जन्म दिया है. लगभग चार माह के ये शावक फिलहाल अपनी मां के साथ जंगल में विचरण कर रहे हैं. इससे यह क्षेत्र एक बार फिर बाघों के सुरक्षित प्राकृतिक आवास के रूप में उभरकर सामने आया है. करीब दो वर्ष पहले भी टीएफ-1 ने चार शावकों को जन्म दिया था. हालांकि उस समय एक शावक सड़क पार करते समय दुर्घटना में मारा गया था. इसके बाद बाघिन ने शेष तीन शावकों का पालन-पोषण इसी क्षेत्र में किया और उन्हें शिकार करने का प्रशिक्षण भी दिया. बड़े होने पर शावकों की आवाजाही खेतों तक बढ़ने से संभावित मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने दो शावकों को बेहोश कर पकड़कर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया था. उस समय यह आशंका जताई जा रही थी कि टीएफ-1 अपना क्षेत्र छोड़ देगी, लेकिन उसने गिरड़-खुर्सापार के जंगल को ही अपना स्थायी आवास बनाए रखा. अब दूसरी बार चार शावकों के जन्म ने इस क्षेत्र की जैव विविधता और संरक्षण क्षमता को और मजबूत साबित किया है.

गंदे पानी से परेशान लोग लेंगे जल सामाधी

आर्वी : आर्वी तहसील के पाचोड (ठा.) गांव में वर्षों से हो रही गंदे एवं दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है. गोर सेना तथा समस्त ग्रामवासियों ने पंचायत समिति के समूह विकास अधिकारी (बीडीओ) को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि आगामी पांच दिनों के भीतर नियमित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो ग्राम पंचायत कार्यालय पर ताला लगाकर परिसर में 'जलसमाधि आंदोलन' किया जाएगा. ग्रामीणों का आरोप है कि, ग्राम पंचायत द्वारा कई वर्षों से गंदा और दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं. इस संबंध में 8 सितंबर 2020, 16 जून 2021 तथा 21 मार्च 2024 को संबंधित विभागों को कई बार लिखित शिकायतें और ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. ज्ञापन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुए कार्यों पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

बंगाली बंधुओं को मिलेगा भूमि का मालकी अधिकार

राजस्व मंत्री बावनकुले का ऐतिहासिक फैसला

संवाददाता / गडचिरोली

गडचिरोली जिले के बंगाली समाज पुनर्वास कानून तहत मिली जमीनों से जुड़ा वर्षों पुराना मामला अब सुलझने की दिशा में बढ़ गया है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पुनर्वास के तहत आवंटित भोगवटादार वर्ग-2 की जमीनों को वर्ग-1 (पूर्ण मालिकाना हक) में परिवर्तित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इस संबंध में विधानभवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. सरकार के इस निर्णय से गडचिरोली जिले की 21,824 एकड़ भूमि का वर्षों पुराना विवाद समाप्त होने की उम्मीद है. इससे जिले के लगभग 40 हजार बंगाली बांधवों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी जमीन पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होगा.

10 हजार घर होंगे नियमित, गांवठाण होंगे पूरी तरह निशुल्कः

बैठक में बंगाली समाज के आवासीय भूखंडों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. जिले में बंगाली समाज के करीब 10 हजार मकानों को नियमित करने के लिए प्रशासन को तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही संबंधित गांवठाण जमीन को पूरी तरह निशुल्क नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी. 40 हजार नागरिकों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव अब तक वर्ग-2 श्रेणी की जमीन होने के कारण बंगाली समाज के लोगों को भूमि की खरीद-बिक्री, बैंक ऋण लेने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. वर्ग-1 का दर्जा मिलने के बाद ये सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त होगा. बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि, प्रस्ताव को युद्धस्तर पर तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए शीघ्र शासन को भेजा जाए, जिससे इस निर्णय का लाभ जल्द से जल्द पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा पाएंगा.

बोर टाइगर पर्यटकों की पहली पसंद 17000 से अधिक पर्यटक पहुंचे

संवाददाता / वर्धा

वर्धा जिले का बोर टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. वर्ष 2025-26 में 30 जून तक 17 हजार से अधिक पर्यटकों ने यहां के कोर और बफर क्षेत्र में जंगल सफारी का आनंद लिया. इससे बोर टाइगर रिजर्व प्रशासन को लगभग 62 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.

वन विभाग के अनुसार, बोर टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र 13,800 हेक्टेयर तथा बफर क्षेत्र 67,814.46 हेक्टेयर में फैला है. वर्ष 2023 से 2025 के दौरान किए गए विशेष सर्वेक्षण में यहां 131 प्रजातियों की आरोही वनस्पतियों का दस्तावेजीकरण किया गया है. यह क्षेत्र बाघों के संरक्षण के साथ-साथ तेंदुए, भालू तथा अन्य शाकाहारी और मांसाहारी वन्यजीवों के लिए भी महत्वपूर्ण आवास माना जाता है. पर्यटकों में बीटीआर-1 अंबिका, बीटीआर-3 कैटरीना और बीटीआर-7 पिंकी जैसे बाघों को देखने का विशेष आकर्षण रहता है.

इन्हीं वन्यजीवों की एक झलक पाने के लिए महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं. बोरधरण स्थित कोर सफारी गेट 1 अक्टूबर से तथा अडेगांव गेट 27 दिसंबर से पर्यटकों के लिए खोला गया था. मानसून को देखते हुए 30 जून से दोनों कोर सफारी गेट बंद कर दिए गए हैं. हालांकि बफर क्षेत्र के ढगा और रहाटी गेट वर्षा ऋतु में भी पर्यटकों के लिए खुले हैं और यहां जंगल सफारी जारी है.

अर्जुनी मोरगांव में झमाझम, अन्य तहसीलों में बरसीं रिमझिम फुहारें

24 घंटे में दर्ज की गई औसतन 8.0 मिमी वर्षा - धान रोपाई के कामों ने पकड़ी रफ्तार

संवाददाता / गोंदिया

गोंदिया जिले में अब बारिश का जोर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। 9 जुलाई को गोंदिया सहित जिले की सभी तहसीलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश होने की जानकारी मिली है। हालांकि दिनभर आसमान में घने बादल छाए रहने के कारण पिछले 8 दिनों से जिले में सूर्य के दर्शन नहीं हुए। बारिश थमने से धान की रोपाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। यह रोपाई वह किसान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने निजी सिंचाई संसाधनों के बल पर जून की शुरुआत में बुआई का काम पूरा कर लिया था। जबकि अभी भी 90 प्रतिशत

से अधिक किसान बुआई के कार्य में ही लगे हुए हैं।

8 जुलाई की रात से 9 जुलाई को सुबह के दौरान जिले की अर्जुनी मोरगांव तहसील में झमाझम बारिश होने की जानकारी मिली है। जबकि अन्य तहसीलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हुई है।

लेकिन इस बारिश से किसान खुश नजर आ रहे है। जिलाधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष से ली गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अर्थात 9 जुलाई को सुबह 10.30 बजे तक गोंदिया तहसील में 10.9 मिमी, आमगांव में 0.7 मिमी, तिरोड़ा में 6.7 मिमी, गोरेगांव में 4.4 मिमी, सालेकसा में 1.2 मिमी, देवरी में 9.0 मिमी एवं सड़क अर्जुनी तहसील में 2.7 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। इस अवधी में सबसे अधिक 20.4 मिमी बारिश अर्जुनी मोरगांव तहसील में दर्ज की गई।

जलाशयों के भंडारण की स्थिति बाघ इटियाडोह सिंचाई विभाग गोंदिया से ली गई जानकारी के अनुसार जिले के प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में बारिश थमने से बढ़ोत्तरी भी कम हो रही है। 9 जुलाई को सुबह 7 बजे तक अर्जुनी मोरगांव तहसील में स्थित इटियाडोह जलाशय में 25.03 प्रतिशत, देवरी तहसील के सिरपुरबांध में 10.37 प्रतिशत, सालेकसा तहसील के कालीसराड़ बांध में 28.98 प्रतिशत एवं पुजारीटोला बांध में 77.06 प्रतिशत जल भंडारण दर्ज किया गया है। मध्यप्रदेश के संजय सरोवर में 25.48 प्रतिशत जल भंडारण दर्ज किया गया है।

वन परिक्षेत्राधिकारी को दी भावभीनी विदाई

उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित

संवाददाता / सालेकसा

गोंदिया वन विभाग के अंतर्गत सालेकसा वन परिक्षेत्र में कार्यरत वनपरिक्षेत्राधिकारी रमेश घोटके को उनकी सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई.

गढ़माता मंदिर ट्रस्ट परिसर में आयोजित समारोह में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, वन प्रबंधन समितियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर उनके कार्यों की सराहना की और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. रमेश घोटके ने 28 दिसंबर 2025 को सालेकसा वन परिक्षेत्र का कार्यभार संभाला था. इससे पूर्व उन्होंने गड?चिरोली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय तक वन विभाग में अपनी सेवाएं दीं. सालेकसा में अपने अल्प कार्यकाल के दौरान उन्होंने वन संरक्षण, अवैध अतिक्रमण हटाने, अवैध मुरूम व रेत उत्खनन, सागौन तस्करी पर रोक लगाने तथा जंगलों को आग से बचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया. उन्होंने वन विभाग, ग्राम पंचायत, वन प्रबंधन समितियों, क्षेत्र सहायकों, वनरक्षकों, वन मजदूरों, राजस्व विभाग के सहयोग से कई जनहितकारी व संरक्षण संबंधी अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए, उनके कार्यकाल में जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर विभागीय कार्यों में उल्लेखनीय गति देखने को मिली. 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता गोंदिया वन विभाग के उपवनसंरक्षक पवन जोग ने की. प्रमुख अतिथियों में सहायक उपवनसंरक्षक सचिन डोंगरवार, नवेगांवबांध के वनपरिक्षेत्राधिकारी मेश्राम, सडक अर्जुनी के वनपरिक्षेत्राधिकारी मिथुन तरोने, गोंदिया के वनपरिक्षेत्राधिकारी राजू कुंभारे सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.

परसवाड़ा में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक्स-रे शिविर आयोजित, 72 लोगों की हुई जांच

संवाददाता / तिरोडा

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, परसवाड़ा में 'मेरा गांव, स्वस्थ गांव' अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निःशुल्क एक्स-रे जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों में क्षय रोग (टीबी) की समय पर पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करना तथा गांव को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में जनजागरूकता बढ़ाना था।कार्यक्रम में पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति एवं सदस्य हुपराज जमईवार मुख्य रूप से

उपस्थित रहे।

शिविर का संचालन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वाती हरिणखेड़े के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवक कार्तिक पटले, स्वास्थ्य सेविका आशा पटले, आशा कार्यकर्ता सीमा कोटांगले, ऊषा ठाकरे तथा प्रतिभा शेंडे सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई।शिविर के अंतर्गत गांव के 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। टीबी की संभावित पहचान के लिए कुल 72 लोगों के छाती के एक्स-रे किए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने उपस्थित नागरिकों को टीबी के लक्षण, बचाव, समय पर जांच तथा नियमित उपचार के महत्व की जानकारी भी दी।इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष ग्रामीणों ने शिविर में भाग लेकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं तथा 'टीबी मुक्त भारत' और 'स्वस्थ एवं समृद्ध गांव' के संकल्प को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग दें। ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता से शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

डीएचओ ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण

आमगांव : 'मेरा गांव, स्वास्थ्य संपन्न गांव' अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार ने आमगांव तहसील का दौरा कर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान डॉ. गोल्हार ने आमगांव ग्रामीण अस्पताल, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बाम्हणी गांव तथा बनगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया. उन्होंने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए सीधे नागरिकों के घरों तक पहुंचकर अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी ली. जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध दवाइयों, भर्ती मरीजों (आईपीडी), औषधि भंडार, टीकाकरण व्यवस्था, वैक्सीन की गुणवत्ता तथा मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की.

तिरोड़ा में 15 से 20 सितंबर तक होगा भव्य श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ

श्री इंद्रेश उपाध्याय महाराज करेंगे अमृतमयी कथा वाचन

संवाददाता / तिरोड़ा

श्री राधा रानी की असीम कृपा से तिरोड़ा शहर में आगामी 15 से 20 सितंबर तक भव्य श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन श्रीधाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेशजी उपाध्याय के श्रीमुख से होगा। इस धार्मिक आयोजन को लेकर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह का माहौल है।आयोजन की शुरुआत 14 सितंबर को प्रातः 10 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। यह कलश यात्रा श्रीराम

राधाकृष्ण गजानन देवस्थान, स्टेशन रोड, तिरोड़ा से प्रारंभ होकर कथा स्थल तक पहुंचेगी। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा एवं धार्मिक ध्वजों के साथ भक्ति-भाव से इस शोभायात्रा में सहभागी होंगे। 15 से 20 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से कथा का आयोजन जिला परिषद कन्या शाला, शहीद स्मारक के सामने, तिरोड़ा में किया जाएगा। छह दिवसीय कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं एवं श्रीमद्भागवत महापुराण के दिव्य प्रसंगों का रसपूर्ण वर्णन किया जाएगा।

धार्मिक आयोजन के अंतर्गत 16 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, 19 सितंबर को गोवर्धन महाराज पूजन तथा राधा अष्टमी (लाड़लीजी सरकार जन्मोत्सव) श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं 20 सितंबर को कथा का विधिवत विश्राम एवं पूर्णाहुति संपन्न होगी।

आयोजन समिति ने समस्त श्रद्धालुओं से इस पावन श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण करने, धर्म लाभ एवं पुण्य प्राप्त करने तथा अपने परिवार एवं समाज के मंगल की कामना के साथ इस आध्यात्मिक महोत्सव का हिस्सा बनने की अपील की है।

गलत दस्तावेज पर बीमा कराने वालों व सीएससी पर होगी कार्रवाई

संवाददाता / गोंदिया

राज्य में पिछले वर्ष सामने आए फर्जी फसल बीमा मामलों के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों को और सख्त कर दिया है. अब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फसल बीमा कराने वाले किसानों के साथ-साथ संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों पर भी सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. दोषी पाए जाने पर कारावास, जुर्माना, आधार नंबर को ब्लैकलिस्ट करने तथा पांच वर्ष तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है. यह जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी निलेश कानवडे ने दी. सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना का लाभ देती है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा का लाभ लेने तथा कुछ सीएससी संचालकों द्वारा गलत जानकारी भरकर शासन से धोखाधड़ी करने के कई मामले सामने आए थे. राज्यभर में ऐसे करीब 4,500 मामले सामने आने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव कर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है. अब फसल बीमा आवेदन भरते समय किसानों द्वारा जमा किए गए आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखना सीएससी संचालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. यह रिकॉर्ड मुआवजा मिलने तक या कम से कम दो वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा. यदि किसी सीएससी केंद्र से फर्जी आवेदन भरे जाने का मामला सामने आता है, तो संबंधित संचालक पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिले में एक हजार से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालित हैं. इन केंद्रों के माध्यम से जमा किए गए फसल बीमा आवेदनों की जांच की जाएगी. यदि किसी किसान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बीमा राशि प्राप्त की है, तो वह राशि उसके आधार से जुड़े बैंक खाते से वसूल की जाएगी. साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

समूचे जिले को आदिवासी जिला घोषित करने की मांग

संवाददाता । गोंदिया

महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी महासंघ ने राज्यसभा सांसद राजेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपकर संपूर्ण गोंदिया जिले को आदिवासी जिला घोषित करने की मांग की है. महासंघ ने केंद्र एवं राज्य सरकार से इस संबंध में आवश्यक पहल करने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष इसकी अनुशंसा करने का आग्रह किया है. महासंघ ने अपने ज्ञापन में बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कुछ जिलों को पहले ही आदिवासी जिला घोषित किया है. इसी तर्ज पर गोंदिया जिले को भी आदिवासी जिला घोषित किया जाना चाहिए. ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि गोंदिया जिला अपनी आदिवासी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत के कारण लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. जिले के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में आदिवासी समदाय निवास करता है.

वृक्षधरा फाउंडेशन का जिप स्कूल में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम

पर्यावरण संरक्षण का लिया सामूहिक संकल्प

संवाददाता / गोंदिया

पर्यावरण संरक्षण व हरित भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से वृक्षधरा फाउंडेशन व शाला व्यवस्थापन समिति, फत्तेपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिला परिषद विद्यालय, फत्तेपुर (गोंदिया) परिसर में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिसमें जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों, विद्यार्थियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की उल्लेखनीय सहभागिता रही.

प्रमुख अतिथि जिप कृषि व पशुसंवर्धन सभापति दीपा सुधीर चंद्रिकापुरे, पूर्व जिप सभापति व पंस सदस्य शैलजा सोनवाने ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया. अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए प्रत्येक नागरिक से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने का आह्वान किया. यह आयोजन शाला व्यवस्थापन समिति के सदस्य किशोर अंबुले ने किया था. कार्यक्रम में ग्रापं फत्तेपुर के सभी ग्रापं सदस्य, शाला व्यवस्थापन समिति सदस्य, आंगनवाड़ी सेविकाएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं, गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी, वृक्षधरा फाउंडेशन के पदाधिकारी, सदस्य व स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज कराई.

धान उत्पादकों को आधुनिक खेती व तकनीकों की दी गई जानकारी

लाखनी : तहसील के मानेगांव में कृषि विभाग की ओर से 'किसान गोष्ठी' का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया. किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों और किसानों के बीच सीधा संवाद हुआ. कार्यक्रम का आयोजन हनुमान मंदिर परिसर में किया गया. इस अवसर पर महाराष्ट्र शासन के प्रतिष्ठित 'खेत मित्र' पुरस्कार से सम्मानित मुखरू बागडे का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया. कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए उपस्थित किसानों ने उनका अभिनंदन किया. कार्यक्रम में कृषिभूषण शेषराव निखाडे, शेती मित्र मुखरू बागडे, प्रगतिशील किसान अर्चना देंगे, भावना भलाई और संजय मेंढे ने अपने खेती संबंधी अनुभव साझा किए. किसानों ने खेती में अपनाई जा रही नई तकनीकों, नवाचारों और सफल प्रयोगों की जानकारी प्राप्त की. साथ ही विशेषज्ञों ने किसानों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया. उपविभागीय कृषि अधिकारी किशोर पात्रीकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक उषा डोंगरवार, परियोजना संचालक उर्मिला चिखले तथा सभापति अश्विनी मोहतुरे ने किसानों का मार्गदर्शन किया. उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से खेती की लागत कम कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. विशेष रूप से धान उत्पादक किसानों से एसआईआर एवं डीएसआर पद्धति अपनाने का आग्रह किया गया, जिससे कम खर्च में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके.

आईडी घोटाले पर श्वेतपत्र जारी करने की उठी मांग

स्कूल शिक्षा एंव खेल विभाग की ओर से शिक्षक संगठन के प्रशासन पर आरोप

संवाददाता / आमगांव

राज्य में चर्चित शालार्थ आईडी घोटाले तथा स्कूल शिक्षा व खेल विभाग के नाम से तैयार किए गए कथित फर्जी शासन पत्रों के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति, मान्यता और वेतन से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार से तत्काल श्वेतपत्र जारी करने की मांग उठी है. यह मांग मुंबई शिक्षक लोकतांत्रिक आघाड़ी, गोंदिया जिला तथा शिक्षक सहकार विभागीय संगठन ने की है. संगठनों का कहना है कि विभिन्न जांच

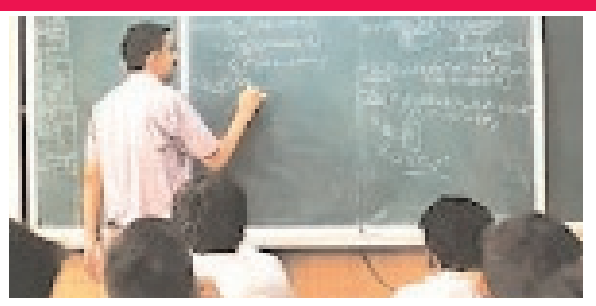

एजेंसियों द्वारा मामले की जांच जारी होने की जानकारी समय-समय पर दी जाती रही है, लेकिन अनेक प्रकरण अब भी लंबित हैं. ऐसे में सरकार की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट न होने से शिक्षकों, शिक्षण संस्थाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों में भ्रम तथा संदेह का वातावरण बना हुआ है.

निधि के दुरूपयोग की आशंका संगठनों ने आरोप लगाया कि कथित शालार्थ आईडी घोटाले और फर्जी शासन पत्रों के माध्यम से सरकारी वेतन निधि के दुरुपयोग की आशंका है. इसके बावजूद

अब तक जांच की वर्तमान स्थिति, दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, सरकार को हुए आर्थिक नुकसान तथा उसकी वसूली के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. ज्ञापन में कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े संस्थानों या प्रभावशाली व्यक्तियों को संरक्षण दिए जाने जैसी आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखनी चाहिए. संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल शिक्षा व खेल विभाग के नाम से तैयार किए गए कथित फर्जी शासन पत्रों के आधार पर कुछ निजी संस्थाओं ने विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक नियुक्तियों को मान्यता दिलाकर सरकारी वेतन निधि का दुरुपयोग किया. इस संबंध में संबंधित विभागों और गृह विभाग को कई शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई है. संगठनों ने मांग की है कि सरकार श्वेतपत्र के माध्यम से शालार्थ आईडी घोटाले और कथित फर्जी शासन पत्रों से जुड़े कुल मामलों की संख्या, लंबित मामलों का विवरण, दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, संस्थाओं व अन्य संबंधित व्यक्तियों पर की गई कार्रवाई, सरकार को हुए आर्थिक नुकसान और उसकी वसूली की जानकारी सार्वजनिक करे. साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए उपायों की भी घोषणा करे.

कार्यालय नगर परिषद तिरोडा जि. गोंदिया

निविदा सूचना (दुसरी वेळ)

दिनांक : ०९/०६/२०२६

मुख्याधिकारी नगर परिषद तिरोडा जि. गोंदिया यांचेमार्फत सन २०२६-२७ करिता खालील कामाची निविदा मागविण्यात येत आहे. कामाचा तपशील तसेच सविस्तर अटी व शर्ती नगर परिषद तिरोडा येथे निविदा सूचना प्रकाशित झाल्यापासून ०७ दिवसाच्या आत पाहण्याकरिता उपलब्ध राहील.

१. नगर परिषद तिरोडा करिता विद्युत साहित्य पुरवठा करणे.

२. नगर परिषद क्षेत्रातील भटक्या डुकरांना पकडणे व त्यांना बाहेर सोडणे.

मुख्याधिकारी
नगर परिषद, तिरोडा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरूनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरूनानक वार्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.
संपादक :- चंद्रकात खंडेलवाल, पी.आर.पी एक्ट के तहत जिम्मेदार *